sectors with strong export potential, encourage diversification of India's export basket, address infrastructure short comings, improve export facilitation measures and thus enhance the overall competitiveness of Indian exports. The Government is according high priority to exports and all necessary steps are being taken to put exports on high growth trajectory.

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में दिये गये ऋण

*87. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जनपदों में वर्ष-वार कितने बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराए गये;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से कितने युवक लाभान्वित हुये?

उद्योग मंत्री (श्री सिकंदर बख्त): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों तथा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में वास्तविक लक्ष्यों को (सहायता दिए जाने वाले युवाओं की संख्या की दृष्टि से) आवंटित करती है। लक्ष्यों का जिला-वार आवंटन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा राजसहायता, प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के लिए निधियां उपलब्ध करके सहायता की जाती है। तथापि, परियोजना के लिए अधिकांश सहायता राशि अभिज्ञात युवाओं हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से प्राप्त होती है।

(ग) इस संबंध में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उपर्युक्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान अखिल भारतीय आधार पर 634775 युवाओं को ऋण का संवितरण किया गया है।

विवरण

1995-96, 1996-97, और 1997-98 के दौरान चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों तथा उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन ऋण लेने वाले बेरोजगार युवाओं की संख्या।

(राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार)

1995-96

क्र॰ सं॰	जिले/राज्य का नाम	योजनागत लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृतियां (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरण (संख्या)	संवितरित राशि (लाख रु॰ में)
1.	चमोली	242	157	154	58.27
2.	पौड़ी गढ़वाल	364	271	193	74.12
3.	टेहरी गढ़वाल	296	247	227	101.91
4.	उत्तर प्रदेश	35813	37324	30819	16727.61

1996-97

क्र० सं०	जिले / राज्य का नाम	योजनागत लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृतियां (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरण (संख्या)	संवितरित राशि (लाख रु० में)
1.	चमोली	242	237	211	85.46
2.	पौड़ी गढ़वाल	364	350	255	85.68
3.	टेहरी गढ़वाल	296	296	260	135.16
4.	उत्तर प्रदेश	35813	37490	30139	16962.67

1997-98

क्र० सं०	जिले / राज्य का नाम	योजनागत लक्ष्य (संख्या)	बैंकों द्वारा स्वीकृतियां (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरण (संख्या)	संवितरित राशि (लाख रु० में)
1.	चमोली	250	250	211	81.92
2.	पौड़ी गढ़वाल	400	336	237	90.45
3.	टेहरी गढ़वाल	350	354	309	167.14
4.	उत्तर प्रदेश	45200	44243	35103	20065.30

Workers' Participation in Management

*88. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal for workers' participation in management;

(b) if so, the steps taken by Government in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) The scheme on Employees Participation in Management which is currently in existence, was prepared and notified in December, 1983. The Scheme is applicable to all Central Public Sector Enterprises except those specifically exempted. It envisages constitution of bipartite fora at shop and plant levels. In enterprises considered suitable, it was also to be implemented at the Board level. The Scheme provides for bipartite consideration of certain work-related issues concerning production, quality, targets, technological improvement, safety, welfare measures, environmental issues, absenteeism, financial performance of the enterprises etc.

The State Government were requested to introduce the 1983 Scheme of Employees Participation in Management in their own Public Sector Undertakings. The Private Sector would also be encouraged to implement the Scheme.

Keeping in view the shortcomings of the various schemes of worker's Participation in Management implemented from time to time and also the experience gained in this regard, the Government decided to review the scheme and to evolve a fresh approach to make worker's participation in management more effective and